भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2105

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मेकेदातु बांध परियोजना

2105. कु. सुधा आर.:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कावेरी नदी के ऊपर, विशेषकर कर्नाटक में किसी नए बांध के निर्माण से कृषि कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और कावेरी डेल्टा जिलों, विशेषकर मयिलादुथुराई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने कावेरी नदी पर मेकेदातु नाम से एक नया बांध बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मेकेदातु बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम, 1956 की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2236(ई) दिनांक 01 जून, 2018 के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया गया ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2018 के आदेश के माध्यम से संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने हाल ही में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी राज्यों के लिए कावेरी बेसिन के तहत आने वाली जल संसाधन परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए "कावेरी बेसिन में जल संसाधन परियोजनाओं के मूल्यांकन" हेतु दिशानिर्देशों को प्रकाशित किया है जिससे सीडब्ल्यूडीटी निर्णय (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित) से संबंधित परियोजना में प्रस्तावित जल उपयोग की अनुकूलता या अन्य को सुनिश्चित किया जाए।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हो चुकी है।

परियोजना प्राधिकरण को परियोजना के कार्यान्वयन से पहले संबंधित विभागों से पर्यावरण मंजूरी सहित सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।

*****